शिमला से प्रकाशित
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक
प्रकाशन का 47 वां वर्ष
ई-पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 47 अंक-29 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 11-18 जुलाई 2022 मूल्य पांच रूपए

मुफ्ती पर प्रधानमंत्री की चेतावनी के परिदृश्य में मुख्य सचिव कैसे अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे

शिमला/शैल। जब मुख्यमंत्री को चुनावों से चार माह पहले भी मुख्य सचिव को बदलने की नौबत आ जाये और ऐसे अधिकारी को इस पद पर लाना पड़ जाये जिसका सेवाकाल भी इतना ही शेष बचा हो तथा इसके लिये तीन सिनियर अधिकारियों को बिना काम के बैठाना पड़े तो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने स्वभाविक हो जाते हैं। क्योंकि यह वह वक्त होता है जब पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री की घोषणाओं को जमीनी हकीकत में बदलने के लिये काम में जुट जाता है। मुख्यमंत्री पिछले 2 माह से लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हर चुनाव क्षेत्र में करोड़ों की घोषणाएं और शिलान्यास हो रहे हैं। इन घोषणाओं की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां सुनिश्चित करना प्रशासन का काम होता है। प्रशासनिक सचिव और वित्त विभाग की इसमें अहम भूमिका रहती है। इस प्रशासनिक प्रक्रिया के संचालन की जिम्मेदारी मुख्य सचिव की रहती है।

ऐसे में जिस तत्परता में नये मुख्य सचिव की नियुक्ति की गयी और उसके लिये इनसे वरीयता में ऊपर के तीन अधिकारियों को नजरअंदाज किया गया है उससे प्रदेश के शीर्ष प्रशासन पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। चर्चा रही है कि पूर्व मुख्य सचिव कई बार मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमण्डल को आश्वस्त कर चुके थे कि वह सत्ता में वापसी सुनिश्चित कर देंगे। शायद इन्हीं आश्वासनों के चलते मुख्य सचिव के खिलाफ पीएमओ से करीब 1 वर्ष पहले आयी शिकायत पर अमल नहीं किया गया। बल्कि इस शिकायत के आने के बाद ही प्रधानमंत्री दो बार हिमाचल आये। अदानी पावर के 280 करोड़ ब्याज सहित लौटाने के मामले के अतिरिक्त ऐसा और कोई मामला

क्या सिनियर अधिकारियों को बिना काम के बैठाना सरकारी धन का दुरूपयोग नही है

भी नहीं था जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोई संज्ञान लिये जाने की संभावना बनती है। मुख्य सचिव का चयन एकदम मुख्यमंत्री का एकाधिकार होता है। फिर जिस अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया गया है उसने तो कुछ दिन पहले मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन कर रखा था और इस चयन के लिए कमेटी की बैठक भी हो गयी थी। इसका अर्थ यह निकलता है कि तब तक मुख्य सचिव को बदले जाने और धीमान को उनके स्थान पर लाने के कोई संकेत तक नहीं थे। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बदलाव की परिस्थितियां अचानक और उस समय बनी जब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पंडित खीमी राम कांग्रेस में शामिल हो गये यह सब जानते हैं कि आधा सिराज मण्डी में तो आधा बंजार में पड़ता है। इसलिये मुख्यमंत्री के लिये सिराज से ज्यादा बाहर निकलना आसान नहीं होगा।

यह राजनीतिक परिस्थिति निर्मित होते ही मुख्यमंत्री के अपने कोर खेमे में चिन्ता की लकीरें उभरना स्वाभाविक थी। चर्चा है कि इस कोर ग्रुप ने तुरंत अपनी बैठक की बल्कि एक सदस्य को तो गाड़ी भेज कर बुलाया गया। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री से इस बदलाव का आग्रह किया गया जिसे मुख्यमंत्री टाल नहीं सके। चर्चा तो यहां तक है कि इस कमेटी का सुझाव तो धीमान को भी नजरअन्दाज करके सीधे सक्सेना को मुख्य सचिव बनाने का था। जिनको नजर अन्दाज किया गया उनमें से कुछ पर तो कांग्रेस की चार्जशीट बनाने में भूमिका होने तक का आरोप भी शायद लगाया गया। शायद इसी आरोप का परिणाम है की नजरअन्दाज हुए अधिकारियों को बिना किसी विभाग के बैठा दिया गया। मुख्यमंत्री को यह तक समझने नहीं दिया गया कि इतने बड़े अधिकारियों को बिना काम के बैठाना जनता के धन का सीधा दुरुपयोग है। बल्किआने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को ओडीआई अधिकारियों की सूची में न रखने को लेकर भी जवाब देना कठिन हो जायेगा। क्योंकि आई एन एक्स मीडिया मामले में वह जमानत पर चल रहे हैं और इस

शेष पृष्ठ 8 पर.........

खीमी राम की सुलगाई आग दूर तक विनाश करेगी

शिमला/शैल। हिमाचल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं मंत्री रह चुके पंडित खीमी राम ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। खीमीराम कांग्रेस में उस सुधीर शर्मा के माध्यम से शामिल हुए हैं जिनको लेकर यह फैलाया जा रहा था कि वह भाजपा में जाने की तैयारी में हैं। भाजपा की ओर से भी लगातार यह फैलाया जा रहा था कि बहुत से कांग्रेसी उनके संपर्क में हैं। लेकिन सुधीर-खीमी के मिलन ने दोनों दलों के समीकरणों को हिला कर रख दिया है। क्योंकि खीमीराम का असर कुल्लु और मण्डी दोनों जिलों में होगा यह तय है। बल्कि सिराज तो आधा मण्डी और आधा बंजार में है और खिमी राम एक तरफ से जयराम पर ही ग्रहण हो जायेगा। खीमीराम के बाद हिमाचल में भाजपा के पूर्व पार्षद मनोज कुठियाला भी कांग्रेस में शामिल हो गये हैं। उन्होंने प्रतिभा सिंह के आवास हॉलीलॉज में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष निक्का सिंह पटियाल ने सुखविन्दर सुक्खु की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इस तरह भाजपा कांग्रेस में सेंध लगाने के जो प्रयास कर रही थी उनके सफल होने से पहले ही भाजपा में टूटन शुरू हो जाना एक बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है।

भाजपा आज टूटन के मुकाम पर क्यों पहुंच रही है? खीमी राम के जाने की भाजपा के त्रिदेव और प्रदेश की गुप्तचर एजैन्सियों तक को भनक न लग सकी यह अपने में एक बड़ी बात है। माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह शिमला में इसी का जायजा लेने पहुंचे थे। इसके लिये संगठन सरकार और प्रभारियों तक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। अब तक मुख्यमंत्री को नड्डा का जो संरक्षण प्राप्त था अब उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगने की नौबत आ गयी है। क्योंकि जब दोनों निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल किया गया था तब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को इसके बारे में पूछा तक नहीं गया। बल्कि इनके शामिल होने को धूमल समर्थकों को ही ठिकाने लगाने का प्रयास किया जाना माना गया। इसकी पुष्टि शिमला और धर्मशाला में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अनुराग ठाकुर को मिले व्यवहार से भी हो जाती है। बल्कि अनुराग ने केजरीवाल की कांगड़ा यात्रा से पहले आप के तत्कालीन संयोजक अनूप केसरी को तोड़कर जिस तरह से सक्रियता का परिचय दिया था वह बाद में अचानक लोप क्यों हो गयी।

यह एक सार्वजनिक सच है कि 2017 में धूमल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से ही भाजपा की सरकार बन पायी है। लेकिन सरकार बनने के बाद धूमल और उनके समर्थकों को जिस तरह से लगातार नजर अन्दाज किया जाता रहा है वह भी सबके सामने है। इस आशय के समाचार लगातार छपते आये हैं कि कई पूर्व विधायकों के टिकट कटेंगे। यह इंगित

शेष पृष्ठ 8 पर.........

राज्यपाल ने शिक्षण संस्थानों की नैक रिपोर्ट जारी की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन और सफलतापूर्वक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आहवान किया है।

राज्यपाल मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों की राज्य स्तरीय विश्लेषण की नैक रिपोर्ट जारी करने के बाद सम्बोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि उनके विचार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे शिक्षा क्षेत्र को उपनिवेशवाद के प्रभाव से मुक्त करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि केवल घोषणा मात्र से इस नीति का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं होगा। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने इस दिशा में प्रशासन के उच्चाधिकारियों को कार्य करने का आहवान किया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर लगभग 87 प्रतिशत है और प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र सराहनीय प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने विशेष बल देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को पाठयक्रम से सम्बन्धित पुस्तकों के अलावा अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की भावना की अहम भूमिका होती है।

इस अवसर पर प्रधान सचिव शिक्षा मनीष गर्ग ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए नैक रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पांचवां राज्य है, जहां राज्यवार नैक रिपोर्ट जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में प्रदर्शन पर आधारित ग्रेडिंग का उल्लेख किया गया है, जो यह दर्शाता है कि प्रदर्शन के अनुसार हमारी स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों की नैक की रैंकिंग में भाग लेना चाहिए ताकि भविष्य में समिति के मापदंडों के अनुरूप कार्य किया जा सके।

नैक की सहायक निदेशक डॉ. विनीता साहू ने भी प्रदेश के व्यावसायिक महाविद्यालयों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आईक्यूएसी के निदेशक प्रो. चन्द्र मोहन परशीरा ने भी अपनी प्रस्तुति दी।

नैक के सहायक निदेशक श्याम सिंह इंदा ने कहा कि यह रिपोर्ट प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जा रही शिक्षा पर आधारित है और गुणवत्ता मानक का संकेतक है।

निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा ने इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राजभवन में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट कर, उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर बधाई दी। उन्होंने इस दौरान राज्य के विकास में उनके मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त किया।

इससे पहले, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों व गणमान्य व्यक्तियों ने भी राजभवन पहुंचकर उन्हें बधाई दी।

राज्यपाल ने अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर राजभवन में यज्ञ का आयोजन किया और परिसर में एक चिनार का पौधा लगाया। उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों के साथ वार्तालाप करते हुए राज्य के लोगों का उनके सहयोग और विभिन्न कार्यों में योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका एक वर्ष का कार्यकाल सुखद और संतोषजनक रहा।

हिमाचल प्रदेश में आईटीआई/एनएसटीआई में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू

शिमला/शैल। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश भर में स्थापित आईटीआई (सरकारी और निजी) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न विषयों में दीर्घकालिक कौशल कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्किल इंडिया मिशन को बढ़ाने के लिए, हिमाचल प्रदेश में भी सत्र 2022-23 के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत आईटीआई / एनएसटीआई के लिए प्रवेश सत्र पहले ही शुरू कर दिया गया है।

एमएसडीई के तहत डीजीटी को कुशल बनाने में व्यवसाय में आसानी के लिए, बाजार/औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार आईटीआई पाठयक्रम को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, परीक्षा प्रक्रिया को सरल बनाया है, तेजी से परिणाम, उसमें रखे गए वैकल्पिक पाठयक्रमों में औद्योगिक अनुभव के लिए नौकरी प्रशिक्षण (ओजेटी) के साथ जोड़ा गया है। आईटीआई के पाठयक्रम में सॉफ्ट स्किल्स और उद्यमिता प्रशिक्षण को शामिल करना। इसके अलावा, आईटीआई के पाठयक्रमों के पूरा होने के बाद, शिक्षुता के लिए आसान एक मात्र क्लिक की पंजीकरण, परिसर साक्षात्कार, उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए दीक्षांत समारोह, कई स्थानीय और वैश्विक नौकरी के अवसरों पाने के लिए के लिए नए कौशल भारत पोर्टल पर एक मात्र क्लिक पंजीकरण आदि की भी सुविधा प्रदान की गई है।

10 वीं पास आईटीआई के छात्रों के लिए, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) या हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (एचपीबीओएसई) के माध्यम से समानांतर 12 वीं कक्षा की परीक्षा की भी सुविधा प्रदान की गई है और 12 वीं पास आईटीआई के छात्रों के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन विश्वविद्यालय के माध्यम से समानांतर स्नातक डिग्री हासिल करने का प्रावधान भी है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) भारत सरकार ने इस संबंध में NIOS और IGNOU के बीच पहले ही एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके तहत इच्छुक पुरुष/महिला/लड़कियां हिमाचल प्रदेश राज्य में आईटीआई /एनएसटीआई में विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उसी के प्रवेश नोटिस पहले ही राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किए जा चुके हैं। विवरण के लिए क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय (RDSDE)- ठाकुर वाटिका (संपर्क नं. 0177- 2626196) लोअर खलिनी, शिमला (हि.प्र.)-171002 से संपर्क किया जा सकता है।

भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेरोजगारी के मुद्दों से निपटने के लिए देश के युवाओं के कौशल पर जोर दिया है और भारत सरकार का कौशल भारत मिशन उसी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) भारत सरकार स्किल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं के 217 पदों पर उप-निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के 217 पदों पर उप-निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि इन 217 पदों में एक पद जिला परिषद सदस्य झाकड़ी-2, जिला परिषद शिमला, 6 पद पंचायत समिति सदस्य, 14 प्रधान, 17 उप-प्रधान तथा 179 पंचायत वार्ड सदस्य के पद रिक्त हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 25,26 व 27 जुलाई, 2022 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इनकी जॉच पड़ताल 28 जुलाई, 2022 को सम्बन्धित रिटर्निंग/ सहायक रिटर्निंग अधिाकारी प्रात: 10 बजे के उपरान्त करेंगे।

इच्छुक प्रत्याशी 30 जुलाई, 2022 को सायं 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 30 जुलाई, 2022 को ही नामांकन पत्रों की वापसि के तुरन्त पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसन्द का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि मतदान 10 अगस्त, 2022 को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जाएगा। प्रधान, उप-प्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मदगणना 10 अगस्त, 2022 को पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद की मतगणना 12 अगस्त, 2022 को खण्ड मुख्यालय पर प्रात: 9 बजे की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के जिला शिमला में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसी प्रकार, जिन विकास खण्डों में पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन होना है, उन विकास खण्डों में तथा जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप-प्रधान एवं सदस्य का निर्वाचन होना है, उन ग्राम पंचायतों में भी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिलावार विवरण हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आदर्श आचार संहिता शहरी निकाय के क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

ड्रोन की खरीद व ड्रोन सेवाओं के लिए दरें निर्धारित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में ड्रोन से सम्बन्धित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गरूड़ परियोजना शुरू की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा विभागों में ड्रोन को बतौर उत्पाद और सेवा के रूप में उपयोग में लाने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को इसकी खरीद दरें निर्धारित करने का कार्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई।

उन्होंने कहा कि ड्रोन की खरीद और उनकी सेवाओं के लिए छः विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया गया है। निगम ने इनमें से चार सूचीबद्ध विक्रेताओं के साथ ड्रोन के माध्यम से निगरानी, सर्वे, आपदा प्रबन्धन, कृषि के लिए ड्रोन के माध्यम से स्प्रे तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया है। उन्होंने कहा कि निगम विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि को सूचीबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी पहुंच, चपलता और उपयोग में आसानी जैसी विशेषताओं के कारण ड्रोन हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर पर दुर्गम और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अन्जना

ऑनलाइन बुकिंग पर भी 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकेंगी महिला यात्री

शिमला/शैल। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रवक्ता ने बताया कि निगम ने एचआरटीसी के अग्रिम आरक्षण पोर्टल पर 14 जुलाई, 2022 से महिला यात्रियों के लिए राज्य के भीतर निगम की साधारण बसों में यात्रा की अग्रिम टिकट बुकिंग पर 50 प्रतिशत छूट की सुविधाा उपलब्ध करवा दी है।

प्रवक्ता ने कहा कि महिला यात्री निगम की वेबसाईट www.hrtchp.com पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा कर निगम द्वारा राज्य के भीतर चलाई जा रही साधारण बसों के टिकट की अग्रिम बुकिंग कर सकती हैं। इस छूट का लाभ उठाने के लिए महिला यात्रियों को अलग से टिकट बुक करना होगा।

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस हमीरपुर का लोकार्पण

किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस को 3.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है, इसका शिलान्यास 6 दिसंबर, 2019 को किया गया था और लोक निर्माण विभाग ने इसे रिकॉर्ड समय में बना कर तैयार किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में ईवीएम वेयरहाउस बनाये जा रहे हैं ताकि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक साथ एक स्थान पर ही रखा जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजकीय महाविद्यालयों और स्कूल परिसरों में रखा जाता था और ऐसी स्थिति में मशीनों के सुरक्षा संबंधी प्रबंध करने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए शिक्षण संस्थानों के कमरों का लंबे समय तक उपयोग होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती थी।

उपायुक्त हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए वेयरहाउस के संबंध में संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री के साथ प्रधान सचिव शिक्षा एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग शिमला में मौजूद रहे, जबकि विधायक नरेंद्र ठाकुर हमीरपुर में समारोह में उपस्थित रहे।

बारदाना पर हुई 6 प्रतिशत जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार वहन करेगी:महेन्द्र सिंह

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमण्डल ने सेब सीजन को दृष्टिगत

बागवानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बारदाना पर हुई 6 प्रतिशत की जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार वहन करेगी।

उन्होंने कहा कि बागवानों को बारदाने पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ रहा था, जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने बागवानों को जीएसटी में 6 प्रतिशत की छूट देते हुए बढ़ी हुई जीएसटी की दर को स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। बागवानों को अब बारदाना 12 प्रतिशत जीएसटी की पुरानी दर पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एचपीएमसी व हिमफैड को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तीन निजी कम्पनियां विभाग से सम्बद्ध है, जो बागवानों को बारदाना उपलब्ध करवाती है। वह भी पुरानी जीएसटी दरों पर ही बागवानों को बारदाना उपलब्ध करवाएगी।

बागवानी मंत्री ने कहा कि मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नीम्बू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा तथा गलगल की खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान करने के साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में समर्थन मूल्य में एक रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी की है।

इस अवसर पर जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के बागवानों का एक प्रतिनिधिमण्डल भी बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर से मिला। बागवानी मंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार बागवानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए संवेदनशील है और सेब सीजन के दौरान बागवानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

हिमाचल में 300 जल भण्डारण का किया जाएगा निर्माण:वन मंत्री

शिमला/शैल। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जल

भण्डारण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

वन मंत्री ने कहा कि योजना के तहत प्रदेश में 300 जल भण्डारण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इनके निर्माण से भूमि में जलस्तर बढ़ने के साथ-साथ जल संरक्षण भी होगा तथा जल भण्डारण संरचनाओं के निर्माण से वनों में उपस्थित वनस्पति को भी लाभ मिलेगा। वन अग्नि रोकथाम में भी इन जल भण्डारण संरचनाओं का उपयोग किया जाएगा। साथ ही इनके निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

राकेश पठानिया ने कहा कि वन विभाग में चलाए जा रहे विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा अनुभव हेतु विभिन्न संस्थानों में भेजा जाएगा।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन बल प्रमुख अजय श्रीवास्तव, राज्य वन निगम के प्रबन्धन निदेशक डॉ. पवनेश, क्षेत्रीय मुख्य अरण्यपाल, अरण्यपाल एवं वन मण्डलाधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे।

75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया जाएगा राष्ट्रव्यापी अभियान-हर घर तिरंगा

शिमला/शैल। आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज समूचे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और राष्ट्र के लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहल लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अन्तर्गत 13 से 15 अगस्त तक हर घर, राजकीय, निजी, औद्योगिक और शैक्षणिक भवनों में तिरंगा फहराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभासीष पन्डा, सचिव भाषा कला एवं संस्कृति राकेश कंवर, निदेशक ग्रामीण विकास रुगवेद ठाकुर, निदेशक भाषा कला एवं संस्कृति डॉ. पंकज ललित आदि उपस्थित थे।

भूमि अधिग्रहण मुआवजा फैक्टर के दृष्टिगत वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ भूमि अधिग्रहण मुआवजा फैक्टर के संबंध में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक ओक ओवर शिमला में आयोजित की गई।

उप समिति ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न फोरलेन एवं अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों के बारे में अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमण्डलीय उप समिति को संशोधित मुआवजा फैक्टर के दृष्टिगत वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से विभिन्न फोरलेन और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की समुचित रूप से पहचान की जाए ताकि किसी भी तरह के अभियोग अथवा परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के समक्ष भी उठाया जाएगा।

बैठक में प्रभावित परिवारों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री एवं मंत्रिमण्डलीय उप समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर, समिति के अन्य सदस्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, वन मंत्री राकेश पठानिया, ऊर्जा मंत्री सुख राम, मुख्य सचिव आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण में 200 करोड़ खुराक लगाने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण में 200 करोड़ खुराक लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर केंद्र सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त एवं सक्षम नेतृत्व और देश की जनता के सक्रिय सहयोग को जाता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने भी कोविड टीकाकरण के तहत 1.33 करोड़ से अधिक की खुराक लगाई है, जो प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत एक सराहनीय उपलब्धि है।

पांच वार्डों में मतदाता सूचियां अपडेट कार्यक्रम पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने आज यहां बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में नगर निगम शिमला के पांच वार्डों में मतदाता सूचियां अद्यतन करने के कार्यक्रम पर आगामी आदेशों तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने पांच वार्डो 6-समरहिल, 9-बालूगंज, 11-टूटीकण्डी, 12-नाभा और 13-फागली की मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का कार्यक्रम जारी किया था। प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इन पांचों वार्डों के परिसीमन पर स्थगन सम्बन्धी आदेशों के उपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग ने उपरोक्त वार्डों में मतदाता सूचियां अद्यतन करने के कार्य को स्थगित करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी है।

राज्य चुनाव आयोग ने इन वार्डों से सम्बन्धित प्राप्त सभी दावों, आपत्तियों एवं शुद्धियों को आगामी आदेशों तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास सुरक्षित रखने के भी निर्देश जारी किए हैं।

हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं।

......स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या मोदी मुफ्ती बन्द करने की शुरूआत अपनी सरकारों से करेंगे

प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने वोटों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपनायी जा रही मुफ्ती संस्कृति के प्रति देश और इसके युवाओं को सचेत किया है। प्रधानमन्त्री ने युवाओं का आहवान करते हुए यह आग्रह किया है कि वह इस संस्कृति का शिकार होने से बचें। प्रधानमन्त्री ने इस मुफ्ती को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिये ही घातक करार दिया है। प्रधानमंत्री की यह चिंता न केवल जायज है बल्कि इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। यह चिंता जितनी जायज है उसी के साथ यह समझना भी उतना ही आवश्यक है कि यह संस्कृति शुरू कैसे हुई? क्या कोई भी राजनीतिक दल और उसकी सरकारें इस संस्कृति से बच पायी हैं? इस संस्कृति पर रोक कौन लगायेगा? क्या प्रधानमंत्री अपनी पार्टी और उसकी सरकारों से इसकी शुरुआत करेंगे? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हर मंच से उठाये जाने आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री यदि ईमानदारी से इस पर अमल करने का साहस जुटा पाये तो इसी एक कदम से उनकी अब तक की सारी असफलतायें चर्चा से बाहर हो जायेंगी यह तय है। क्योंकि मुफ्ती का बदल सस्ता है। मुफ्ती से कुछ को लाभ मिलता है जबकि सस्ते से सबको इससे फायदा होता है। मुफ्ती ही भ्रष्टाचार का कारण बनती है। आज पड़ोसी देश श्रीलंका में जो हालात बने हुए हैं उसके कारणों में यह मुफ्ती भी एक बड़ा कारण रही है। प्रधानमन्त्री की यह चिन्ता उस समय सामने आयी है जब रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक मन्दी तक पहुंच गया है। रुपये की इस गिरावट का असर आयात पर पड़ेगा। जो बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने गये हैं उनकी पढ़ाई महंगी हो जायेगी। इस समय हमारा आयात निर्यात से बहुत बढ़ चुका है। शेयर बाजार से विदेशी निवेशक अपनी पूंजी लगातार निकलता जा रहा है। इससे उत्पादन और निर्यात दोनों प्रभावित हो रहे हैं तथा बेरोजगारी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी निवेशक 18 लाख करोड़ तक का निवेश निकाल सकता है। रिजर्व बैंक देश के 13 राज्यों की सूची जारी कर चुका है। जिनका कर्ज इतना बढ़ चुका है कि वहां कभी भी श्रीलंका घट सकता है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एक बैठक में प्रधानमन्त्री को इस बारे में सचेत कर चुके हैं। इस समय देश का कर्ज भार 681 बिलियन डॉलर हो चुका है और अगले नौ माह में 267 बिलियन की अदायगी की जानी है। जबकि इस समय विदेशी मुद्राभण्डार 641 बिलियन डॉलर से घटकर 600 बिलियन तक आ पहुंचा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक वर्ष बाद 267 बिलियन डॉलर कर्ज की अदायगी के बाद विदेशी मुद्रा भण्डार जब आधा रह जायेगा तब महंगाई का आलम क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है यह प्रधानमन्त्री के बयान के बाद भक्तों और विरोधियों दोनों को स्पष्ट हो जाना चाहिये। मोदी सरकार को 2020 के अन्त में बैड बैंक बनाना पड़ा था और दो लाख करोड़ का एनपीए रिकवरी के लिये इसे दिया गया था। अब इस प्रयोग के बाद संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय बैंकों को प्राइवेट सैक्टर को देने का विधेयक ऐजैण्डे पर आ चुका है। इसका परिणाम बैंकिंग पर क्या होगा? इसका अंदाजा लगाने के लिये यह ध्यान में रखना होगा कि 2014 से डिपाजिट पर लगातार ब्याज दरें कम होती गयी हैं। क्योंकि बैंकों का एनपीए बढ़ता चला गया। सरकार ने नोटबंदी से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को कर्ज के माध्यम से उबारने के जितने भी प्रयास किये उसके परिणाम स्वरूप बैंकों ने सरकार के निर्देशों पर कर्ज तो दिये लेकिन इनकी वापसी नहीं हो पायी। अकेले प्रधानमन्त्री ऋण योजना में ही 18.50 लाख करोड़ का कर्ज बांट दिया गया। इसमें कितना वापस आया और इसके लाभार्थी कौन हैं इसकी तो पूरी जानकारी तक नहीं है। उज्जवला और गृहिणी सुविधा योजनाओं में मुफ्त गैस सिलैण्डर तो एक बार वोट के लिये बांट दिये गये। लेकिन यह सिलैण्डर रिफिल भी हो पाये या नहीं इस पर ध्यान नहीं गया। जनधन में जीरो बैलेंस के बैंक खाते तो खुल गये परंतु क्या सभी खाते ऑपरेट हो पाये यह नहीं देखा गया। व्यवहारिक स्थिति यह है कि 2019 का चुनाव इन मुफ्ती योजनाओं के सहारे जीत तो लिया गया लेकिन आगे आर्थिकी इतनी सक्षम नहीं रह पायी की एक बार फिर मुफ्ती में नया कुछ जोड़ा जा सके। बल्कि आज इस मुफ्ती से श्रीलंका घटने का खतरा मंडराने लग पड़ा है। प्रधानमन्त्री की मुफ्ती को लेकर आयी चिन्ता इसी संभावित खतरे का संकेत है। बल्कि अब मुफ्ती को कानून बनाकर रोकने का साहस करना पड़ेगा और यह शुरुआत प्रधानमन्त्री को अपने दल और अपनी सरकारों से करनी पड़ेगी।

भारतीय समावेशी राष्ट्रवाद के दुश्मन हैं डॉ. इलियास

गौतम चौधरी

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी की मस्जिद इंतेजामिया समिति को ज्ञानवापी मामले में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक कानूनी समिति के गठन की घोषणा की। इससे पहले नवंबर 2019 में, एआईएमपीएलबी ने अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया था। दोनों मामलों में जो बात ध्यान देने योग्य है, वह है डॉ. एसक्यूआर इलियास का ससला। इलियास एआईएमपीएलबी कार्यकारी सदस्य है और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का भी सदर है।

डॉ. इलियास इन दिनों इस मामले को लेकर अत्यधिक उत्साह और मामले में व्यापक उपस्थिति दर्ज करा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी एआईएमपीएलबी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं लेकिन इन दिनों नोमानी साहब के बदले डॉ. इलियास मामले में मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे हैं। इलियास के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भारत सरकार के खिलाफ जबर्दस्त अभियान चलाया जा रहा है। देश विरोधी और पृथकतावादी बातों को हवा दिया जा रहा है। इस्लामिक चरमपंथ का समर्थन किया जा रहा है और उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। देश को बांटने वाले एजेंडों का प्रचार किया जा रहा है। इस बात को एआईएमपीएलबी को गंभीरता से लेना चाहिए और एक बार इलियास के अतीत की जांच भी कर लेनी चाहिए।

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला है कि ज्ञानवापी कानूनी आयोग के सदस्य डॉ. इलियास का संबंध प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन सिमी के साथ रहा है। सिमी को इलियास कानून कानूनी सहायता प्रदान करते रहे हैं। इलियास ने सिमी में अपना कार्यकाल अंसार (पूर्णकालिक सदस्य) के रूप में शुरू किया और 1983-85 के बीच इसके अध्यक्ष भी रहे। सिमी पर प्रतिबंध लगाने के बाद, डॉ. इलियास चालाकी दिखाई और जमात ए इस्लामी हिंद में चले गए। बता दें कि भारत में मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा का पालन करने वाले जमात ए इस्लामी हिंद को देश के कई शहरों में सीएए विरोधी प्रदर्शन आयोजित करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था। इस संगठन से जुड़े लोगों ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के कदम का भी विरोध किया था।

डॉ. इलियास के साथ सहानुभूति रखने वाले अधिकांश लोगों को यह नहीं पता है कि इलियास ने सिमी को वैचारिक मतभेद के कारण नहीं अपितु 30 की आयु सीमा पार करने के कारण उसे छोड़ा था पर आज भी वे सिमी के सदस्यों के वैचारिक केन्द्र बिन्दु बने हुए हैं। जानकारी में रहे कि सिमी में 30 की आयु के बाद नहीं रहा जा सकता है। यह उस संगठन का नियम है। इसी नियम के तहत उन्होंने सिमी छोड़ा। सिमी छोड़ने के बाद भी, उन्होंने संगठन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाए रखा। 2003 में, डॉ. इलियास ने सिमी का बचाव किया जब उसके कार्यकर्ता "राष्ट्रवाद को नष्ट करो और खिलाफत स्थापित करो" के नारे दिए थे। वे इसका पोस्टर लेकर आगे आए।

यहां यह भी बता दें कि इन पोस्टरों के कारण दो सिमी कार्यकर्ताओं को पोटा (आतंकवाद रोकथाम अधिनियम) के तहत पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। डॉ. इलियास के दुस्साहस और कट्टरपंथी मानसिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभियुक्तों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद उग्रवाद का एक रूप है, उस समय उन्होंने अपने एक पोस्टर के माध्यम से यह भी कहा था कि खिलाफत का अर्थ है ईश्वर की इच्छा के राज्य की स्थापना।

ऐसे चरमपंथी विचारों वाले डॉ. इलियास को अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कानूनी समिति का सदस्य बनाया गया है। यह एक खुला तथ्य है कि जहां अधिकांश भारतीय मुसलमानों ने देश की शांति और सद्भाव बनाये रखने के लिए अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, वहीं कुछ मुट्ठी भर राजनीति से प्रेरित डॉ. इलियास जैसे व्यक्तियों ने इसका विरोध किया और एक समीक्षा याचिका दायर की और कड़ी मेहनत से प्राप्त की गई शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की गयी।

ज्ञानवापी मामले का अंतिम परिणाम जो भी हो, सिमी के साथ अपने पिछले जुड़ाव और उसकी लगातार बढ़ती कट्टरपंथी मानसिकता को देखते हुए डॉ. इलियास जैसे लोगों से आपसी सदभाव की कल्पना नहीं की जा सकती है। इलियास जैसे लोग नफरत को बढ़ावा देते ही रहेंगे। भारत के मुसलमानों को इस प्रकार के नफरत परस्तों से सावधान रहना चाहिए। डॉ. इलियास जैसे लोग भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इनके उपर ईरान के कट्टरवादी समूहों के साथ संबंध का भी आरोप लगता रहा है।

वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग रोकने वाले हिमालयी ग्लेशियरों के अनूठे मामले को सुलझाया

शोधकर्ताओं ने इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है कि काराकोरम रेंज में ग्लेशियरों के कुछ हिस्से ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनदों को पिघलने से क्यों रोक रहे हैं और पूरे विश्व में ग्लेशियरों (हिमनदों) का द्रव्यमान खोने की उस प्रवृत्ति को कैसे झूठला रहे हैं जिसका हिमालय भी कोई अपवाद नहीं है। उन्होंने 'कराकोरम विसंगति' नामक इस घटना को पश्चिमी विक्षोभ (डब्ल्यूडी) के अभी हाल में हुए पुनरुद्धार के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

हिमालय के ग्लेशियरों का भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से उन लाखों निवासियों के लिए जो अपनी दैनिक जल आवश्यकताओं के लिए इन बारहमासी नदियों पर निर्भर करते हैं, बहुत महत्व है। ये ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण तेजी से कम हो रहे हैं। आने वाले दशकों में जल संसाधनों पर दबाव कम करना बहुत जरूरी है। इसके विपरीत, पिछले कुछ दशकों से मध्य कराकोरम के ग्लेशियर आश्चर्यजनक रूप से या तो अपरिवर्तित रहे हैं या उनमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। यह घटना ग्लेशियोलॉजिस्टों को हैरान कर रही है और जलवायु परिवर्तन से इंकार करने वालों को भी इस बारे में कुछ नहीं सूझ रहा है।

इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआई एसईआर) भोपाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पंकज कुमार ने इस घटना को बहुत अजीबोगरीब पाया है क्योंकि यह व्यवहार बहुत छोटे क्षेत्र तक ही सीमित पाया गया है, पूरे हिमालय में केवल कुमलुम पर्वतमाला में इसी तरह के रुझान दिखाने का एक और उदाहरण मिलता है।

उनकी देखरेख में अभी हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने क्षेत्र के अन्य ग्लेशियरों के प्रतिकूल कुछ क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के विपरीत एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है।

अमेरिकन मेटियोरोलॉजिकल सोसाइटी के जर्नल ऑफ क्लाइमेट में प्रकाशित एक पेपर में, उनके समूह ने यह दावा किया कि 21वीं सदी के आगमन के बाद से कराकोरम विसंगति उत्प्रेरित करने और बनाए रखने में पश्चिमी विक्षोभ का अभी हाल में हुआ पुनरुद्धार बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अध्ययन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम द्वारा भी समर्थन दिया गया था।

यह पहली बार हुआ है कि एक अध्ययन उस महत्व को सामने लाया है जो संचय अवधि के दौरान उस डब्लूडी-वर्षा इनपुट को बढ़ाता है जो क्षेत्रीय जलवायु विसंगति को संशोधित करने में भूमिका निभाता है।

डॉ. कुमार के पीएच.डी. छात्र आकिब जावेद और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक ने कहा कि डब्ल्यूडी सर्दियों के दौरान इस क्षेत्र के लिए बर्फबारी के प्राथमिक फीडर हैं। हमारे अध्ययन से यह पता चलता है कि इनका कुल मौसमी हिमपात की मात्रा में लगभग 65 प्रतिशत और कुल मौसमी वर्षा में लगभग 53 प्रतिशत योगदान हैं, जिससे वे आसानी से नमी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं। कराकोरम को प्रभावित करने वाले डब्ल्यूडी की वर्षा की तीव्रता में पिछले दो दशकों में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो केवल क्षेत्रीय विसंगति को बनाए रखने में अपनी भूमिका में बढ़ोत्तरी करती है।

समूह ने पिछले चार दशकों में कराकोरम-हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले डब्लूडी की एक व्यापक सूची को ट्रैक और संकलित करने के लिए तीन अलग-अलग वैश्विक रीएनालिसिस डेटासेट के लिए एक ट्रैकिंग एल्गोरिदम (रीडिंग विश्वविद्यालय में विकसित) लागू किया है। कराकोरम से गुजरने वाली ट्रैक के विश्लेषण से पता चला है कि बड़े पैमाने पर संतुलन के आकलन में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में बर्फबारी की भूमिका रहती है।

पिछले अध्ययनों में हालांकि वर्षो से विसंगति को स्थापित करने और बनाए रखने में तापमान की भूमिका पर प्रकाश डाला है और ऐसा पहली बार हुआ है कि विसंगतियों को पोषित करने में वर्षा के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। शोधकर्ताओं ने विसंगति के पोषण में वर्षा के प्रभाव का भी निर्धारण किया है।

वैज्ञानिकों की गणना से यह पता चलता है कि हाल के दशकों में काराकोरम के मुख्य ग्लेशियर क्षेत्रों में हिमपात की मात्रा के डब्ल्यूडी के योगदान में लगभग 27 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि गैर-डब्ल्यूडी स्रोतों से होने वाली बारिश में लगभग 17 प्रतिशत की कमी आई है जो एक बार फिर उनके दावों को मजबूत करती है।

डॉ. कुमार ने कहा कि यह विसंगति एक हल्की सी लेकिन अपरिहार्य देरी की दिशा में एक उम्मीदभरी आशा की किरण प्रदान करती है। विसंगति को नियंत्रित करने में डब्ल्यूडी की पहचान होने के बाद उनके भविष्य का व्यवहार हिमालय के ग्लेशियरों के भाग्य का अच्छी तरह फैसला कर सकता है।

भारत एक शहरी पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है:हरदीप सिंह पुरी

शिमला। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत एक शहरी पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और राष्ट्रपति भवन एवं अन्य स्मारकों का अतुलनीय स्थापत्य स्वतंत्रता पूर्व के भारत की स्थापत्य विशेषज्ञता को दर्शाता है। पुरी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के 168वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।

पुरी ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों को अंजाम दिया है और वह निर्माण प्रबंधन के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक, सीपीडब्ल्यूडी ने राजधानी क्षेत्र और देश के अन्य हिस्सों के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में कई बदलाव देखे हैं।

मंत्री महोदय ने कहा कि ब्रिटिश शासन के दिनों से लेकर आजादी के बाद और अब 21वीं सदी तक, सीपीडब्ल्यूडी की उपस्थिति निरंतर और आश्वस्तकारी रही है। किसी संस्था का वास्तविक चरित्र इस बात से परिलक्षित होता है कि वह समय के साथ अपने आप को कितनी अच्छी तरह ढाल लेती है। उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के समय से ही सीपीडब्ल्यूडी राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हुआ है।

पुरी ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक व संसद भवन जैसी अन्य समान रूप से प्रतिष्ठित परियोजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास किया। पुरी ने कहा कि आज भी यह संस्था सेंट्रल विस्टा परियोजना के जरिए नए संसद भवन, वीपी एन्क्लेव और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का विकास कर शासन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने कहा, सीपीडब्ल्यूडी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि वह राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर गया है। सीपीडब्ल्यूडी ने अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण किया है और यह अफगान लोगों के साथ भारत की अटूट मित्रता का प्रतीक है।

पुरी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में सीपीडब्ल्यूडी की भूमिका में एक बार फिर सुधार दिखाई दे रहा है। जब भी कोई सुधार और संशोधन होता है, तो उसके साथ कुछ कठिनाइयां भी आती हैं और वे ऐसे लोगों से आती हैं जिनका गतिविधियों में निहित स्वार्थ होता है। आज हम जो निर्माण कर रहे हैं वह सिर्फ आज और कल के लिए नहीं बल्कि अगले 250 वर्षों के लिए कर रहे हैं। इसलिए गुणवत्ता को लेकर कोई भी कमी हमें बहुत महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में आपके पास समान स्तर की प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत महामारी के बाद की दुनिया में सफलतापूर्वक पांव रख रहा है, निर्माण भारत को एक लचीले, टिकाऊ और समावेशी भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुरी ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हो रही है कि सीपीडब्ल्यूडी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ संरचनाओं को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसी प्रौद्योगिकी जो निर्माण जीवनचक्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करती हैं और इस काम में स्वदेशी व स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग होता है।

मंत्री ने सीपीडब्ल्यूडी के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया।

इस अवसर पर पुरी ने सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया और संशोधित वेबसाइट के छह मॉड्यूल भी लॉन्च किए।

'आजादी का अमृत महोत्सव' पर एनएचएआई चलायेगा देशव्यापी पौधरोपण अभियान

शिमला। आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की योजना 17 जुलाई 2022 को देशव्यापी पौधरोपण अभियान आयोजित करने की है। इसका उद्देश्य एक दिन में पूरे देश में लगभग एक लाख पौधों का रोपण करने का प्रयास है। एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पास एनएचएआई के लैंड पार्सलों तथा टोल प्लाजा पर 100 स्थानों को पौधरोपण के लिए चिन्हित किया है। एनएचएआई का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर 15 अगस्त 2022 तक 75 लाख पौध रोपण का लक्ष्य हासिल करना है।

केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मंत्रालय तथा एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी पौधरोपण अभियान में भाग लेंगे। पर्यावरण स्थिरता का संदेश फैलाने के लिए इस अभियान में जनप्रतिनिधि, स्थानीय सिविल सोसाइटी के लोग, स्वयंसेवी संगठन तथा कॉलेज के विद्यार्थी भाग लेंगे। पौधरोपण और उनके रखरखाव के लिए राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम तथा आंध्रप्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को भी शामिल किया जाएगा।

एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास पर्यावरण अनुकूल करने के लिए समय-समय पर पौधरोपण अभियान चलाता रहा है। इसका विजन राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और वन तथा बागवानी के माध्यम से कन्सेसनरियों, राज्य सरकार की एजेंसियों, निजी पौध रोपण एजेंसियों, महिला स्वयंसेवी समूहों को सामूहिक रूप से शामिल करके राष्ट्रीय राजमार्ग के इर्द-गिर्द पौधरोपण को पूर्णता तक पहुंचाना है।

सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी में 11 विषयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

मण्डी में दूसरे राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्चत्तर शिक्षा सर्व सुलभ बनाने की दिशा में कारगर कदम

प्रदेश के 35 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों छात्रों को घर-द्वार के समीप मिल सकेगी उच्च शिक्षा

शिमला। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में उच्चत्तर शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही केंद्र सरकार से रूसा के माध्यम से प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग कर उच्च शिक्षण संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से संपन्न किया जा रहा है। मण्डी में दूसरे राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्चत्तर शिक्षा सर्व सुलभ बनाने की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा।

हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 1970 में पहले राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना राजधानी शिमला में की गयी थी। इस विश्वविद्यालय ने उच्चत्तर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हिमाचली प्रतिभा को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाई और यहां से निकल कर युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों की छाप छोड़ी।

इस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का उत्तरोत्तर विस्तार होता गया और शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। नये महाविद्यालय प्रदेश में खोले गए। ऐसे में विश्वविद्यालय पर शैक्षणिक व प्रशासनिक बोझ बढ़ता जा रहा था और काफी समय से राज्य में सरकारी क्षेत्र में एक अन्य विश्वविद्यालय की जरूरत महसूस की जा रही थी। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्चत्तर शिक्षा के प्रसार में काफी सहायता मिली, लेकिन दूसरे राज्य विश्वविद्यालय की आवश्यकता बनी रही।

वर्तमान प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में सत्ता संभालने के उपरांत मण्डी में शंकुल (क्लस्टर) विश्वविद्यालय की स्थापना कर प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के युवाओं को घर के समीप उच्चत्तर शिक्षा की सुविधा की ओर पहला कदम बढ़ाया। अब इस विश्वविद्यालय को विस्तार देते हुए प्रदेश के दूसरे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एक अप्रैल, 2022 को अस्तित्व में आया और 28 जून, 2022 को मुख्यमंत्री ने मण्डी में इसका विधिवत लोकार्पण किया।

सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी के अंतर्गत पांच जिलों कांगड़ा, चम्बा, कुल्लू, लाहौल-स्पिति और मण्डी के 141 राजकीय एवं निजी महाविद्यालय आएंगे। इनमें 68 राजकीय महाविद्यालय, 36 बी.एड. कॉलेज व 8 संस्कृत महाविद्यालयों सहित अन्य महाविद्यालय शामिल हैं। शेष सात जिलों शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सिरमौर, सोलन एवं किन्नौर के 160 महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अधीन रहेंगे।

भौगोलिक दृष्टि से देखें तो चम्बा के पांगी-भरमौर से लेकर लाहौल-स्पिति के दूरदराज क्षेत्रों से युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने शिमला पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विशेष तौर पर लड़कियों को इतनी दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजने में अभिभावक कई बार आनाकानी कर देते थे। अब मण्डी में विश्वविद्यालय की स्थापना से उनका सफर घटकर आधे से भी कम रह गया है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला 33 विधानसभा क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षा प्रदान करेगा। वहीं, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी प्रदेश के 35 विधानसभा क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अपने छुटपुट शैक्षणिक कार्यों के लिए अब अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनके बहुमूल्य समय के साथ ही धन की भी बचत होगी।

दूसरे राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्चतर शिक्षा के विभिन्न विषयों में सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। सीमित सीटों या अन्य कारणों से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर युवा अब उच्चतर शिक्षा के लिए नियमित कक्षाओं में प्रवेश ले सकेंगे। इस विश्वविद्यालय में शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग के विभिन्न पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है, जिससे प्रदेश के उच्च शिक्षित युवाओं को रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं।

प्रारम्भ में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी में 11 विषयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें एम.ए. इतिहास व लोक प्रशासन, एम.बी.ए., एम.बी.ई., एम. सी.ए., एम.एससी. बॉटनी, कैमिस्ट्री, एन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी तथा एम.एससी. इंडस्ट्रियल कैमिस्ट्री शामिल हैं।

नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही प्रदेश सरकार मौजूदा शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करने की ओर भी विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में उच्चत्तर शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (रूसा) लागू किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 231 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 176 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा 92 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए। इनमें 90 प्रतिशत केंद्रीय भाग एवं 10 प्रतिशत राज्य का भाग है। इसमें से 20 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अधोसंरचना अनुदान, 26 कॉलेजों को 52 करोड़ रुपये का अधोसंरचना अनुदान, एक नए मॉडल डिग्री कॉलेज को 12 करोड़ रुपये तथा दो अन्य डिग्री कॉलेजों को आदर्श कॉलेज बनाने के लिए 8 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से हिमाचल में उच्चत्तर शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत विस्तार सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश के मध्य में स्थित एवं उच्चत्तर शिक्षा में नित नए सोपान चढ़ रहे मण्डी जिला में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक के उपरांत अब प्रदेश के दूसरे राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना से यह सांस्कृतिक नगरी अब उच्चत्तर शिक्षा के मुख्य केन्द्र के रूप में उभर रही है।

दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा मुहैया करवाने में मददगार बनकर कीमती जान बचाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दें नेक व्यक्तिः बिक्रम सिंह

शिमला/शैल। राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक यहां उद्योग, परिवहन, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा व कुशल परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

बैठक को सम्बोधित करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक है और एक अनुमान के अनुसार इनमें से 50 प्रतिशत लोगों को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर (गोल्डन आवर) तत्काल जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने पर बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय मददगार बनने वाले नेक व्यक्ति की भलमनसाहत और मान-सम्मान को सरकार द्वारा कानूनी अधिकार देकर पूरी सुरक्षा प्रदान की है। उसकी इच्छा के विरूद्ध न तो कोई पूछताछ की जाएगी न ही उसका अस्पताल में रूकना जरूरी है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सड़क दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति को हर सम्भव तत्काल चिकित्सा मुहैया करवाने में मददगार बनकर उसकी कीमती जान बचाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दें।

बिक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा हिमाचल सड़क सुरक्षा कोष और गतिविधि नियम, 2022 अधिसूचित किया है जिसके तहत सड़क सुरक्षा उपायों और गतिविधियों का कार्यान्वयन एवं सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा पर 18.38 करोड़ रुपये निधि जारी की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए 28.52 करोड़ रुपये की सड़क सुरक्षा कार्य योजना प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग के अधीन सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसमें लोक निर्माण, परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं। दुर्घटना सम्भावित ब्लैक स्पॉट का एनएचएआई एवं लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सुधार किया जा रहा है। शराब सेंसर और स्पीड चौक रडार के लिए पुलिस विभाग को 75 लाख रुपये जारी किए गए हैं। वाहनों की गति सीमा का पुनः निर्धारण किया गया है। उन्होंने परिवहन विभाग को राज्य व जिला स्तर पर होने वाली जागरूकता गतिविधियों में परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य शैक्षणिक संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र सोलन के सहयोग से सड़क सुरक्षा पर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और आगामी शैक्षणिक सत्र में छठी से दसवीं कक्षा तक इसे पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग को तीन करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार की परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए यात्री वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए निगरानी केंद्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर ट्रॉमा सेन्टरों की स्थापना भी की जा रही है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि गत साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में परिवहन विभाग ने 1985.93 करोड़ रुपये का राजस्व विभिन्न शीर्षों से अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 512.10 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है और प्रथम तीमाही में विभाग ने कुल 182.78 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 85.70 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा मोटर वाहन नियमों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध 129570 चलान कर 22.28 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि एकत्रित की गई है।

उन्होंने कहा कि कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑपरेटरों को 164.12 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता एवं छूट प्रदान की है। इसमें स्टेज कैरिज, कान्ट्रैक्ट कैरिज व शैक्षणिक संस्थानों की बसों के टोकन टैक्स, विशेष पथकर व यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट शामिल है।

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि सड़कों पर पैदल पथ का प्रावधान करने के साथ ही एकीकृत परिवहन प्रबंधन व्यवस्था व ट्रैफिक पुलिस स्टेशन समय की आवश्यकता है। शिमला में ट्रैफिक वॉलंटियर जैसे नवोन्मेषी प्रयोग सभी जिलों तक ले जाने चाहिए।

प्रधान सचिव परिवहन ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा संवेदनशील विषय है और परिवहन विभाग अन्य विभागों के समन्वय से इसे सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने सभी संबद्ध विभागों से आग्रह किया कि वे समन्वय एवं समीक्षा बैठकों में प्राप्त सुझावों पर कार्य करते हुए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना सहयोग दें।

बैठक में गैर सरकारी सदस्यों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप ने परिवहन मंत्री एवं सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव घनश्याम चंद ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। अतिरिक्त आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा हेमिस नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अभिषेक त्रिवेदी, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता, निदेशक स्वास्थ्य अनीता महाजन सहित परिषद के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

साढ़े चार साल कुछ नही किया अब बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में जुटे मुख्यमंत्रीःप्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बदलाव की लहर चार उप चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत से शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट और मजबूत है जो आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी जीत का परचम लहरायेगी।

हमीरपुर में कांग्रेस की नव चिंतन संकल्प रैली को सम्बोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से आमजन परेशान

है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को इसकी कोई चिंता नही है। उन्होंने कहा कि भाजपा न तो महंगाई पर कोई बात करती है और न ही बेरोजगारी पर। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के चलते हजारों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला भाजपा का एक बड़ा घोटाला है जिसमें करोड़ो रुपये का लेनदेन हुआ है। उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर लिपा पोथी कर भाजपा अपने लोगों को बचाने में लगी है।

प्रतिभा सिंह ने सेना में अग्निपथ योजना को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय नही होने देगी।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज प्रदेश 80 हजार करोड़ के कर्ज के बोझ तले दब गया है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत ही गम्भीर हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने साढ़े चार साल के इस कार्यकाल में कुछ नही किया अब कि चुनाव नजदीक आते देख मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में जुटे है जबकि उन्हें पूरा करने के लिये सरकार का खजाना पूरी तरह खाली है।

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सत्ता का मोह त्याग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नही है। सबका अपनी डफली अपना राग है।

मुकेश ने कहा कि भाजपा प्रदेश में रिवायत बदलने की बात कह रही है जबकि प्रदेश के लोगों ने भाजपा को घर बिठाने का पूरा मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की भी जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी।

कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ और फरेब की राजनीति करती आई है और अब यह बात पूरी तरह साबित भी हो चुकी है।

सुक्खू ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह मुद्दों पर कोई बात नही करती। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा सरकार की कारगुजारियों से कोई भी खुश नही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने लोगों का आहवान किया कि वह कांग्रेस को भारी मत्तो से जीता कर विधानसभा में भेजें जिससे प्रदेश को भाजपा के कुशासन से मुक्ति मिल सकें।

प्राकृतिक कृषि पद्धति पर शोध एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का संसाधन केन्द्र स्थापित करने का आग्रहःवीरेंद्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित राज्यों के कृषि एवं बागवानी मंत्रियों के दो दिवसीय

राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के उपरांत यहां बताया कि सम्मेलन में हिमाचल में कृषि व बागवानी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय को दोगुना करने के विज़न को साकार करने के लिए कृषि की दशा और दिशा तय करने पर सार्थक चर्चा की गई। प्रदेश ने इस सम्मेलन के माध्यम से कृषि से जुड़े विभिन्न विषय केन्द्रीय कृषि मंत्री के समक्ष उठाए। हिमाचल में हिमालय क्षेत्र की प्राकृतिक कृषि पद्धति पर शोध एवं विकास के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संसाधन केन्द्र स्थापित करने का आग्रह किया गया।

प्रदेश में बीज आलू के उत्पादन का विषय उठाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व सिस्ट नेमाटोड से प्रभावित होने के कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इसका उत्पादन रोक दिया गया था। उन्होंने अनुरोध किया कि इसका उत्पादन पुनः शुरू करना आवश्यक है और प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां सिस्ट नेमाटोड का प्रकोप नहीं है, वहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तपोषित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाए।

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्राकृतिक कृषि निश्चित रूप से रसायनिक कृषि का ऐसा विकल्प है, जो खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा और समृद्ध किसान से आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने का माध्यम बन सकता है। हिमाचल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश ने प्राकृतिक खेती में पहल करते हुए जून, 2018 से अब तक एक लाख 74 हजार किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया है और एक लाख 71 हजार किसानों ने 10 हजार हेक्टेयर भूमि में रसायनमुक्त खेती शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसी वर्ष से जापान और भारत की सहायता से एक हजार करोड़ रुपये की लागत से जाइका चरण दो फसल विविधिकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2029 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों की आय को बेसलाइन पर प्रति हेक्टेयर 62409 रुपये से बढ़ाकर दो लाख 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम से लगभग 10 हजार किसानों को लाभ होगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने सम्मेलन में एकीकृत कृषि मॉडल के विषय पर चर्चा करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, ग्रामीण विकास एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों को एक समग्र दृष्टि से देखते हुए एकीकृत मॉडल की दिशा में आगे बढ़ना होगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसान परिवार को एक ही है, जो खेती करता है लेकिन अलग-अलग विभाग उसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाते हैं, जो बहुत बार समानान्तर, विरोधाभासी, आपस में प्रतियोगी या किसान हित से परे हो जाती हैं।

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की चुनौती से पार पाते हुए प्रदेश के मेहनतकश किसानों ने बेमौसमी सब्जियों, फूलों, परम्परागत अनाजों और फलों के उत्पादन में अपनी अलग पहचान बनाई है। हिमाचल प्रदेश कश्मीर के बाद देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। डबल इंजन सरकार की किसान बागवानों के लिए कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में भी हिमाचल अग्रणी रहा है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार और ई-नाम में पीएम एक्सीलेंस इन सिविल सर्विस अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पद भरने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पद भरने का निर्णय लिया गया। इन 500 पदों में से चिकित्सा अधिकारियों के 300 पद एक माह के भीतर व क-इन-इंटरव्यू और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पद अनुबंध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया।

बैठक में दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में दंत चिकित्सा अधिकारियों के 19 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से 50 प्रतिशत पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और 50 प्रतिशत बैचवाइज आधार पर भरे जायेंगे।

बैठक में सिरमौर ज़िला के कफोटा में खण्ड चिकित्सा कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नीम्बू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल की खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान करने के साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में एक रुपए प्रति किलोग्राम वृद्धि को भी मंजूरी प्रदान की।

इस योजना के अंतर्गत आम की सभी किस्मों के लिए 250 मीट्रिक सीडलिंग, 500 मीट्रिक टन ग्राफिटिड और 500 मीट्रिक टन आचारी आम 10.50 रुपए की दर से खरीदे जायेंगे। इन्हें हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड और हिमफैड के माध्यम से 1.30 रुपए प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क की दर के साथ खरीदा जाएगा।

मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत लगभग 144936 मीट्रिक टन सेब की खरीद 10.50 रुपए प्रति किलो दर से तथा 2.75 रुपये प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क के साथ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत फल उत्पादकों की मांग के अनुरूप 305 खरीद केंद्र खोले जायेंगे जिनमें से 169 केन्द्र हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा और 136 संग्रह केंद्र हिमफैड द्वारा खोले और संचालित किए जायेंगे।

इसी प्रकार 500 मीट्रिक टन किन्नू, माल्टा और संतरा बी ग्रेड 9.50 रुपये की दर से और सी ग्रेड 9 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 100 मीट्रिक टन गलगल 8 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। इसके तहत सिट्रस फलों के लिए हैंडलिंग चार्ज 2.65 रुपये प्रति किलो और गलगल के लिए एक रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।

प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 18 से 27 जुलाई, 2022 तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने का निर्णय भी लिया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10,11,12 और 13 अगस्त, 2022 तक बुलाने के लिए राज्यपाल को संस्तुति करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार एवं आजीविका परियोजना को बाह्य सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से एशियन विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपये का ऋण समझौता हस्ताक्षरित करने को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना एशियन विकास बैंक के 760.77 करोड़ रुपये के ऋण और हिमाचल प्रदेश सरकार की 338.12 करोड़ रुपये की निधि द्वारा वित्त पोषित है जिसमें एशियन विकास बैंक का हिस्सा 69.2 प्रतिशत और प्रदेश सरकार का 30.8 प्रतिशत होगा।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के थुनाग में जल शक्ति वृत्त खोलने सहित इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में जल शक्ति विभाग में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 26 पद भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जूनियर स्केल आशुलिपिकों के 25 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के रक्कड़ और कोटला बेहड़ में उप मण्डल कार्यालय (नागरिक) खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिला की औट तहसील के किगस, बमसोई और ओडीधार में आवश्यक पदों के सृजन के साथ तीन नए पटवार वृत खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में सिरमौर जिला की पांवटा साहिब तहसील के अंतर्गत मौजूदा पटवार वृत्तों के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की गई। क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से देवी नगर, गोंदपुर, छछेटी, पटलियोन, बैकूं, शमशेरपुर, मानपुर देवरा, खोदरी, मोहकमपुर नावदा, बनौर और टंडन में 11 नए पटवार वृत्त के अतिरिक्त राजपुरा और भटनवाली में दो नए कानूनगो वृत तथा राजपुर और खोरोवाल में दो नई उप तहसीलें खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पांवटा साहिब तहसील में कुल 23 पटवार वृत्त और 4 कानूनगो वृत हो जायेंगे।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला की नाहन तहसील के काला अम्ब, शिमला जिला की चिड़गांव तहसील के अंतर्गत धमवाड़ी, शिमला जिला की रोहड़ू तहसील के अंतर्गत समरकोट में और कांगड़ा जिला की पालमपुर तहसील के चचियां में नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के धर्मपुर और संधोल में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकारी भूमि को एक रुपये प्रतिवर्ष की लीज पर 99 वर्षों के लिए हस्तातंरित करने/लीज पर देने का निर्णय लिया।

बैठक में धर्मशाला और मण्डी के रेंज मुख्यालयों में 2 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में मण्डी जिला के सराज क्षेत्र के देवधार, कुल्लू जिला के कटराई क्षेत्र और सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र के टिम्बी में जल शक्ति विभाग की तीन निरीक्षण कुटीर बनाने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति मण्डल थुरल के अंतर्गत डूहक और टम्पा में नए जल शक्ति अनुभाग खोलने को मंजूरी प्रदान की। इन अनुभागों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के परिसर में बोटेनीकल सर्वे आफ इंडिया का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय की 6.6 एकड़ भूमि 99 वर्षों के लिए एक रुपये टोकन लीज पर बोटेनीकल सर्वे आफ इंडिया के पक्ष में करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के नव-अधिग्रहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल की बैठक में जिला मण्डी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निशु में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने और यहां तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में ऊना जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सन्हाल व धमांदरी में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने और यहां 5 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला के राजकीय उच्च विद्यालय पनवी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकीय सोवा रिग्पा महाविद्यालयों और संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं) विनियम-2017 के प्रावधानों के तहत बेचलर ऑफ सोवा रिग्पा मेडिसन एण्ड सर्जरी प्रदान करने के लिए जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित परमपावन दलाई लामा के संस्थान मेन-त्सी-खांग सोवा रिग्पा कॉलेज एवं अस्पताल तथा तिब्बती चिकित्सा एवं खगोल संस्थान को मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिले के कलाथा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने सहित तीन पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के कसुम्पटी क्षे़त्र के सीपुर में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में डिस्पेंसर के तीन पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला फोरेंसिक इकाई बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में फिंगर प्रिंट एग्जामीनर के तीन पदों को साईंटिफिक अस्सिटेंट में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया।

बैठक में मण्डी में लोक निर्माण विभाग का नया विद्युत तृतीय वृत्त खोलने और आवश्यक पदों का सृजन कर उन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले के मकरीड़ी में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मण्डल खोलने और नौ पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

बैठक में राज्य के 53 अस्पतालों में वेब आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के डिजाइन, विकास और क्रियान्वयन के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, नोएडा को चयनित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोल में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिला के चियुणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संदासू को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत कर, विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

बैठक में शिमला जिला की ग्राम पंचायत मशोबरा के कनोला में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल की बैठक में कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही दो पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के तातियाना, खड़काहन और शिल्ली अधोग में आवश्यक पदों के सृजन के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कुल्लू जिला की मनाली तहसील के बबेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ, विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला की बंजार तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुशैणी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र जिभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के सूरी में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमलेहड़ और बधेहड़ा राजपुताना को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरखुवाला-2 को 10 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैंज को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने और यहां विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल की बैठक में जिला सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिपुरधार को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ ही इस स्वास्थ्य संस्थान के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सिरमौर जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र जरग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में सिरमौर जिले में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ूखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल की बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला के रायसन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिस्तर क्षमता बढ़ाकर 30 बिस्तर करने का निर्णय लिया गया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सीबीआई की धमकी के परिपेक्ष में कांग्रेस का आरोप पत्र कितना प्रभावी होगा इस पर लगी निगाहें

शिमला/शैल। कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने की घोषणा की है। यह दावा किया है कि आरोप पत्र तैयार है और पूरे दस्तावेजी परमाणों से लैस है। कांग्रेस का यह दावा कितना सही निकलता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन इस दावे पर मुख्यमंत्री की अपरोक्ष में यह प्रतिक्रिया आना कि वह पूर्व की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आये भाजपा के आरोप पत्र की जांच सीबीआई को सौंपने से परहेज नहीं करेंगे। यह सही है कि अब तक न तो कोई आरोप पत्र कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ सौंपा है और न ही इस सरकार ने अपनी ही पार्टी द्वारा रस्मी औपचारिकता निभाते हुए पूर्व कि कांग्रेस के खिलाफ सौंपे गये आरोप पत्रों पर कोई कारवाई की है। जबकि भाजपा ने तो चुनाव प्रचार की शुरुआत ही हिमाचल मांगे जवाब पोस्टर जारी करके की थी। अब इस संभावित आरोप को लेकर जो प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की इस तरह से आयी है उससे स्पष्ट हो जाता है कि भ्रष्टाचार को लेकर यह सरकार कतई गंभीर नहीं है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि तुम मेरे बारे में चुप रहो मैं तुम्हारे बारे मुह बन्द

भ्रष्टाचार के हमाम में सब बराबर के नंगे है

रखूंगा। वरना कोई भी मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह का ब्यान देने की हिम्मत नहीं कर सकता। वैसे तो भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और भाजपा सरकारों का चलन एक बराबर रहा है। किसी के भी खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर स्कोर सैटल करने के अतिरिक्त कोई भी सरकार आगे नहीं बढ़ी है। यह भी बराबर रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर दोनों दलों की सरकारों ने एक बराबर कारवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की रस्म को जयराम सरकार ने भी पूरी तरह निभाया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस के दावे केवल जनता को भ्रमित करने के लिये होते हैं। स्मरणीय है कि 31 अक्तूबर 1997 को तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन सहयोग मांगते हुए एक इनाम योजना अधिसूचित की थी। इसमें वायदा किया गया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आयी हर शिकायत पर एक माह के भीतर प्रारंभिक जांच की जायेगी। यदि इस जांच में शिकायत में लगाये गये आरोप संज्ञेय पाये जाते हैं तब इस पर नियमित जांच की जायेगी और प्रारंभिक जांच के बाद ही 25% इनाम राशि शिकायतकर्ता को दे दी जायेगी। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड यह है कि इस योजना के तहत आयी एक भी शिकायत पर एक माह के भीतर प्रारंभिक जांच नहीं हो पायी है।

बल्कि इस अधिसूचित हुई योजना के तहत बनाये जाने वाले नियम आज 25 वर्षों में भी सरकार नहीं बना पायी है। न ही इस योजना को सरकार आज तक वापस ले पायी है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरैन्स के दावे/वायदे करना केवल जनता को गुमराह करने से अधिक कुछ नहीं रह गये हैं। गौरतलब है कि आज जयराम सरकार भी इस हमाम में बराबर कि नंगी हो गयी है। क्योंकि 31 अक्तूबर 1997 को अधिसूचित हुई इस योजना के तहत 21 नवंबर 1997 को ही कुछ शिकायतें सरकार के पास आ गई थी। पर इन पर किसी भी सरकार में योजना के अनुसार कारवाई न होने पर यह मामला 2000 में प्रदेश उच्च न्यायालय में भी पहुंच गया। उच्च न्यायालय ने भी तुरंत जांच पूरी करने के निर्देश दिये। जिन पर आश्वासनों से अधिक कुछ नहीं हुआ। संयोगवश उसके बाद इसी पर शिकायत का मसौदा एसजेवीएनएल के एक प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 18 सितम्बर 2018 को इस पर फैसला देते हुये दोषियों के कृत्य को फ्रॉड करार देते हुये इसमें दिये गये लाभों को 12% ब्याज सहित रिकवर करने के निर्देश दिये। जयराम सरकार ने तत्कालीन सचिव सतर्कता संजय कुंडू को फैसले की कॉपी लगाकर प्रतिवेदन सौंपा गया। जिस पर कारवाई होना तो दूर प्रतिवेदन का जवाब तक नहीं दिया गया है। यह प्रसंग पाठकों के सामने इसलिये रखा जा रहा है कि आज जो कांग्रेस को सीबीआई का डर दिखाकर चुप करवाने का प्रयास किया जा रहा है वह जनता को भ्रमित करने से अभी कुछ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस और सरकार दोनों को पता है कि आज जो आरोप पत्र सौंपा जायेगा उसका मकसद चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने से अधिक कुछ नहीं होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसको कितना नंगा कर पाता है।

मुफ्ती पर प्रधानमंत्री की

........पृष्ठ 1 का शेष

संबंध में प्रदेश उच्च न्यायालय में एक शिकायत लंबित चल रही है।

शीर्ष प्रशासन की इस वस्तुस्थिति के परिपेक्ष में नवनियुक्त मुख्य सचिव कैसे तालमेल बिठाकर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कैसे विश्वसनीयता के दायरे में ला पाते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सरकार मुफ्ती की घोषणा के दम पर वोटरों को लुभाने का जुगाड़ कर रही है और प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह कर रखा है कि वह इस मुफ्ती के प्रलोभन में न आयें। प्रधानमंत्री ने इसे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिये घातक करार दिया है।

केजरीवाल पर प्रधानमंत्री के हमले से आप की प्रदेश इकाई की चुप्पी सवालों में

शिमला/शैल। क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपनी चुनावी उपस्थिति दर्ज करा पायेगी? यह सवाल पिछले कुछ समय से पूछा जाने लगा है। क्योंकि पंजाब में मिली सफलता के सहारे जिस आगाज से पार्टी ने प्रदेश में दस्तक दी थी और यह दावा किया गया था कि दो लाख लोगों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुख्यमंत्री के गृह जिले मण्डी में रैली करके पहला शक्ति प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री को उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में घेरने का दावा किया था। लेकिन पार्टी की दूसरी रैली कांगड़ा में होने से पहले ही इस के तत्कालीन संयोजक अनूप केसरी और दो अन्य नेताओं को अनुराग ठाकुर ने भाजपा का सदस्य बना कर सारी बाजी ही पलट दी। इसके बाद पार्टी को नई प्रदेश कार्यकारिणी बनाने में समय लगा और इसी दौरान हिमाचल के प्रभारी रहे सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद प्रदेश ईकाई अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पायी है। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा को मुद्दा बनाने का जो मंत्र प्रदेश इकाई को दिया था अब उसका जाप भी लगभग बंद हो गया है। अब प्रदेश ईकाई पंजाब का नाम लेना भी भूल रही है क्योंकि एक तो वहां पर उपचुनाव हार गयी और फिर जिस तरह से पंजाब में राघव चड्डा को सलाहकार कमेटी का मुखिया बनाया गया तथा उस पर पंजाब में ही सवाल उठ गये। उसका भी हिमाचल की इकाई पर असर पड़ा है क्योंकि प्रदेश के नेताओं को यह समझ ही नहीं आ पा रहा है कि वह इसका क्या जवाब दें। यही नहीं जिस दिल्ली मॉडल के सहारे हिमाचल में सत्ता के सपने लिये जाने लगे थे अब जब प्रधानमंत्री ने उस मॉडल पर हमला करते हुए मुफ्ती को भविष्य के लिए घातक करार देकर केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी है। प्रधानमंत्री के इस हमले से निश्चित रूप से पार्टी की योजनाओं पर अंकुश और प्रश्न चिन्ह दोनों एक साथ लगने की स्थिति पैदा हो गयी है। पार्टी की बढ़त पर यह एक बड़ा हमला है और प्रदेश का कोई भी नेता इसके जवाब में मुंह नहीं खोल रहा है जबकि इसी मॉडल के पोस्टर हर प्रचार अभियान में बांटे जा रहे हैं। शायद इससे हटकर प्रदेश नेतृत्व के पास और कुछ भी नहीं है। यह लोग प्रदेश सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। इससे यह संदेश जा रहा है कि प्रदेश इकाई के नेतृत्व को प्रदेश की समस्याओं की कोई जानकारी ही नहीं है या फिर कुछ लोगों की निष्ठाएं अभी भी संघ भाजपा के साथ बनी हुई है। क्योंकि अब तक यह लोग कांग्रेस को ही निशाने पर लेकर चल रहे थे और भाजपा भी इन्हें खुला हाथ दिये हुए थी। परंतु अब जब प्रधानमंत्री ने सीधे केजरीवाल पर निशाना साध दिया है उससे आप एक बड़ा वर्ग हताशा में आ गया है जबकि इस समय बदले में प्रधानमंत्री पर बड़े सवाल दागना समय की मांग बन गया है।

खीमी राम की सुलगाई

........पृष्ठ 1 का शेष

सीधे धूमल समर्थकों की ओर रहा है। ऐसे में जिन भी लोगों ने अभी सक्रिय राजनीति से रिटायर होने का फैसला नहीं कर रखा है उन्हें अपने लिये नया आश्रय तलाश करना स्वाभाविक है। फिर धूमल भी अपने समर्थकों को किस आधार पर नजर अन्दाजी के बाद भी संगठन में बैठे रहने को कह सकते हैं। इसलिये इन लोगों के लिये कांग्रेस ही एकमात्र मंच रह जाता है। फिर अभी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मुफ्ती योजनाओं को देश के लिये घातक करार दिया है उस परिदृश्य में आने वाले समय में जयराम को भी ऐसी घोषणाएं वापिस लेनी पड़ेगी अन्यथा यह माना जायेगा कि प्रधानमंत्री का यह उपदेश दूसरे दलों के लिये है भाजपा के लिये नही। उस स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिक्रिया उठेगी वह पार्टी के लिये बहुत घातक होगी और प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं चाहेंगे।